



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 1996/चैत्र 13, 1918

No. 138]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 1996/CHAITRA 13, 1918

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1996

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व-अपवंचन को रोकने के लिए

आयकर

भारत गणराज्य

और

फिलीपीन गणराज्य

के बीच

अभिसमय

मा.का.नि. 173 (अ) चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपीन गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित अभिसमय, उक्त अभिसमय के अनुच्छेद-29 के अनुसार उक्त अभिसमय को लागू करने के लिए दोनों ही संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक-दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात् 21 मार्च, 1994 को प्रवृत्त हो गया है;

भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपीन गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व-अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से,

इसलिए अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की श्रृंखला 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद-1

व्यक्तिगत क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद-2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय प्रत्येक संविदाकारी राज्य की ओर से आय पर लगाए गए करों पर लागू होगा, भले ही उनको आयद करने का तरीका कुछ भी क्यों न हो।
2. कुल आय पर, अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर कर के रूप में समझा जाएगा, जिन में चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण में प्राप्त होने वाले अमलाओं पर कर तथा उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल रकम पर कर भी शामिल है।
3. जिन करों पर यह अभिसमय लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :—

(क) भारत में :

- (1) आयकर जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत लगाया गया कोई अधिभार भी शामिल है;
 - (2) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अंतर्गत लगाया गया अतिकर;
- (जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा)।

(ख) फिलीपीन में :

फिलीपीन गणराज्य की सरकार द्वारा लगाए गए आयकर (जिन्हें इसके बाद "फिलीपीन कर" कहा जाएगा)।

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा मारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा मौजूदा अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएं। संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए जाते हैं।

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय में जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है—भारत का राष्ट्र-क्षेत्र और उसमें शामिल है राज्य-क्षेत्रीय समूह और उसके ऊपर का वायु मण्डलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून/संयुक्त के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा श्रेष्ठाधिकार हों;

(ख) "फिलीपीन" शब्द से अभिप्रेत है—फिलीपीन गणराज्य और जब इसका किसी भौगोलिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो इस का अर्थ है फिलीपीन गणराज्य को समाविष्ट करने वाला राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा फिलीपीन अभिप्रेत है;

(घ) "कर" शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा फिलीपीन कर अभिप्रेत है, लेकिन इसमें कोई ऐसी रकम शामिल नहीं होगी जो करों के संबंध में किसी भूल या चूक के संबंध में देय है जिसके लिए यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदण्ड को निरूपित करते हैं;

(ङ) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कंपनी और अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कर कानूनों के अंतर्गत कोई अन्य कराधेय इकाई शामिल है;

(च) "कंपनी" शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कर कानूनों के अंतर्गत एक कंपनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "मक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है—भारत में केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि; और फिलीपीन के मामले में, वित्त सचिव अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(अ) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है—किसी संविदाकारी राज्य की नागरिकता प्राप्त कोई व्यक्ति और उस संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से अपनी हैसियत प्राप्त करने वाला कोई विधिक व्यक्ति, भागीदार अथवा संस्था;

(अ) "अन्तरराष्ट्रीय घातायात" पद से अभिप्रेत है—किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, निवाय उस स्थिति के जब उक्त जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो।

2. जहाँ तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अधिसूचना के प्रयोजन का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन कर्तों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अधिसूचना लागू होता है।

अनुच्छेद-4

निवासी

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानून के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण, वहाँ पर कर लगाया जा सकता है। लेकिन इस पद में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में उसके स्रोतों से प्राप्त आय पर ही उस राज्य में कर लगता है।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहाँ उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी;

(क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ उसे कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर (सहत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) है;

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके सहत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसके पास दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं हो,

तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो, अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे;

3. जहाँ व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है।

जहाँ वास्तविक प्रबंध-स्थान को तय नहीं किया जा सकता हो, वहाँ सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

अनुच्छेद-5

स्थायी संस्थापन

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ किसी उद्यम का कारोबार संपूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) प्रबंध-व्यवस्था का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा;

(ग) कोई कार्यालय;

(घ) कोई कारखाना;

(ङ) कोई कार्यशाला;

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;

(छ) प्राकृतिक संसाधनों की खोज का कोई स्थान;

(ज) कोई भवन-स्थान, निर्माण परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्य-कलाप जहाँ, ऐसा स्थल परियोजना अथवा कार्यकलाप छः माह से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है;

(झ) कोई भाण्डागार जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएँ मुहैया करता हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :—

- (क) उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ भुवि-धाराओं का प्रयोग;
- (ख) केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना,
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं का केवल कचरे करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (ङ) उद्यम के लिए केवल किसी प्रारंभिक अथवा सहायक स्वरूप के कार्यकलाप चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) में उल्लिखित कार्य-कलापों के मात्र संयोजन के लिए कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामतः कारोबार के निश्चित स्थान के समग्र कार्यकलाप प्रारंभिक अथवा सहायक स्वरूप के हों।

4. किसी व्यक्ति को, जो एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो (किसी स्वतंत्र हैसियत के अधिकर्ता से भिन्न जिस पर पैराग्राफ-6 लागू होता है) प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना समझा जाएगा, यदि;

- (क) उसे उक्त उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आमतौर से उस राज्य में प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उस व्यक्ति के कार्यकलाप इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित उन कार्यकलापों तक सीमित नहीं हों, अथवा
- (ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार न ही हो, परन्तु वह प्रथमोक्त राज्य में आमतौर पर माल का अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो अथवा
- (ग) इस प्रकार के कार्य में वह उद्यम के लिए उद्यम का माल अथवा पण्य-वस्तुओं का उस राज्य में निर्माण करता है, अथवा उन्हें संसाधित करता है।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम, सिवाय पुनर्बीमा के संबंध में, के बारे में यह समझा जाएगा कि वह दूसरे राज्य में कोई स्थायी संस्थापन रखता हो यदि वह उस राज्य के क्षेत्र में प्रथमोक्त वस्तु रखता है अथवा किसी कर्मचारी के माध्यम से अथवा किसी ऐसे प्रतिनिधि के माध्यम से उस राज्य में अवस्थित जोड़ियों का बीमा करता है जो किसी स्वतंत्र हैसियत का कोई अधिकर्ता नहीं हो।

6. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में दलाज, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। लेकिन जब इन तरह के किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा अधिकांश रूप से पूर्णतः उद्यम की ओर से किए जाते हों तो इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत उसे एक स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा, यदि वह प्रमाणित हो जाता है कि एजेंट और उद्यम के बीच लन-वेन भिन्न स्थिति के अर्थों में नहीं किया गया था। ऐसे मामले में पैराग्राफ 4 के उपबंध लागू होंगे।

7. यदि कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा उससे नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो दूसरे राज्य (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) में कारोबार करती हो तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी अपने आप में दूसरी कंपनी का एक स्थायी संस्थापन नहीं मानी जाएगी।

अनुच्छेद-6

अचल सम्पत्ति में आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी की आय भी शामिल है) में प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी दशा में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, भूत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए, अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार। जलयान, नौकाएं तथा विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किगाए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर, तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

व्यापारिक लाभ

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उमी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके केवल उतने अंश पर ही कर लगाया जा सकेगा जितना कि उस स्थायी संस्थापन के कारण हो।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभों को उस स्थायी संस्थापन के लाभ समझा जाएगा जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उन व्ययों को कटौतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हों, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हैं।

4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों में अनुभाजित किए जाने के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए माने जाने वाले लाभों को तब करने की प्रथा रही है, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य को कर लगाने वाले लाभों के ऐसी प्रथागत अनुभाजन-पद्धति के आधार पर निर्धारण से प्रतिबोधित नहीं करेगी, लेकिन अपनाई गई अनुभाजन-पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार होगा।

5. कोई लाभ केवल इस कारण में किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी गई हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों का तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारण किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां लाभों में आय की वे मर्दे शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद-8

विमान परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान के परिचालन से प्राप्त लाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान-परिचालन से किसी संविदाकारी राज्य के अंदर अर्जित स्रोतों से प्राप्त हुए लाभों पर प्रथमोक्त राज्य में उसके आंतरिक कानूनों के अनुसार कर लगेगा लेकिन लगाए गए इस प्रकार के कर को चालीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा। तथापि, किसी भी अवस्था में लगाया गया ऐसा कर किसी तीसरे देश के किसी निवासी द्वारा समान परिस्थितियों में उसी प्रकार के प्राप्त लाभों पर लगाए गए फिलीपीन कर की न्यूनतम दर से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध, किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन अभिकरण में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-9

जहाजरानी

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन से किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों पर उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के परिचालन से किसी संविदाकारी राज्य के अंदर स्रोतों से अर्जित हुए लाभों पर प्रथमोक्त राज्य में उसके आंतरिक कानून के अनुसार कर लगेगा, लेकिन लगाए गए इस प्रकार के कर को चालीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा। तथापि, किसी भी अवस्था में लगाया गया ऐसा

कर किसी तीसरे देश के किसी निवासी द्वारा समान परिस्थितियों में उसी प्रकार के प्राप्त लाभों पर लगाए गए किली-पीन कर की न्यूनतम दर से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तराष्ट्रीय परिचालन अभिकरण में भाग लेने में प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-10

सम्बद्ध उद्यम

1. जहाँ :

(क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(ख) वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं, और दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हों जो उन शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हों, तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की दशा में, उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और उस पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहाँ एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है—और तदनुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के लाभों को सम्मिलित करता है जो प्रथमोक्त राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होंगे यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें इस तरह की होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के मध्यम अधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद-11

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिस राज्य का निवासी अदा करने वाली कंपनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

(क) लाभांशों की सकल रकम का 15 प्रतिशत, यदि हितभागी स्वामी कोई ऐसी कंपनी है, जो लाभांश अदा करने वाली कंपनी के कम से कम 10 प्रतिशत शेयरों की स्वामी हो ;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल रकम का 20 प्रतिशत।

यह पैराग्राफ ऐसे लाभों के मामले में कंपनी के करधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिनमें से लाभांश अदा किए जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांश" पद का अर्थ है—शेयरों से अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण-दावे नहीं हों और जो लाभों में सम्मिलित हों, तथा अन्य निर्गमित अधिकारों से प्राप्त आय जिस पर किसी प्रकार की करधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जम राज्य की वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से उसमें स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं करता हो और वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं, इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हों। ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद-7 तथा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को इस प्रकार के लाभांश अदा नहीं किए जाते अथवा जहां तक कि वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं, उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन से अथवा किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित नहीं है अथवा कंपनी के अधिनिर्गित लाभों पर लगाया जा सकने वाला अवितरित लाभों संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा भले ही अदा किए गए लाभांशों अथवा अवितरित लाभपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद-13

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उक्त दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में यह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभारित कर की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

- (क) व्याज की सकल राशि का 10 प्रतिशत, यदि ऐसा व्याज किसी वित्तीय संस्था (जिसमें बीमा कंपनियां भी शामिल हैं) द्वारा प्राप्त किया जाता है;
- (ख) किसी ऐसी कंपनी द्वारा जो फिलीपीन की निवासी है भारत के किसी निवासी को बंधपत्रों के मार्ब-जनिक निर्गम, ऋणपत्रों अथवा इसी प्रकार की-वाध्यताओं के संबंध में अदा किए गए व्याज पर फिलीपीन कर व्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; और
- (ग) अन्य सभी मामलों में व्याज की सकल राशि का 15 प्रतिशत।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होने हुए भी :

- (क) किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले व्याज पर उक्त राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, अर्थात् कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा हितभागी रूप से रखा गया हो :
 - (i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका राजनीतिक उपप्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा
 - (ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का सेट्टल बैंक;
 - (iii) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों में यथा विनिर्दिष्ट और सहमति-प्राप्त उधार देने वाली अन्य संस्थाएं।
- (ख) किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न व्याज पर उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनु-मोदित सीमा तक उक्त राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, यदि वह (उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित किसी व्यक्ति से भिन्न) किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से धारण किया जाता है जो दूसरे संविदाकारी

राज्य का निवासी है, वरन् कि ऋण-दावा उत्पन्न करने वाले लेन-देन को प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा इस बारे में अनुमोदित किया गया हो।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “व्याज शब्द से अभि-प्रेत है—प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, जिसमें किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उप-करण की क्रेडिट पर विक्री से प्राप्त आय भी शामिल है, चाहे वे गिरवी रखे जाने के द्वारा सृजित हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋणदाता के लाभों से भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और खासतौर पर, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार भी शामिल हैं। विलम्ब से की गई अदायगी के लिए अर्थदण्ड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए राज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज का हितभागी स्वामी, जो एक संविदा-कारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज उद्भूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उक्त दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं करता है, और जिस ऋण-दावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो, वह दावा इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 या 15 के उपबंध, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में व्याज उद्भूत हुआ माना जाएगा, जब व्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा निवासी हो। किन्तु जहां व्याज अदा करने वाला व्यक्ति, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान रखता है जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर व्याज की अदायगी की जाती है, और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का व्याज उस संविदा-कारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां व्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण व्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए व्याज की उक्त रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा-कर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती,

यहां उस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गई रकमों के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों को सम्यक् ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाना रहेगा।

अनुच्छेद-13

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसी रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत होती हैं और उसी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायल्टियों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसी रायल्टियां भुगतान योग्य हों :—

(i) फिजीपीत के मामले में, किसी ऐसे उद्यम द्वारा जो निवेश बोर्ड के पास पंजीकृत है; और

(ii) भारत के मामले में, भारत सरकार द्वारा द्वारा अनुमोदित किसी सहयोगी करार के अनुसरण में किसी उद्यम द्वारा।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “रायल्टियां” शब्द में साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों का कोई स्वत्वाधिकार जिनमें चलचित्र फिल्मों अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के संबंध में प्रयुक्त फिल्मों अथवा टेपों भी शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिनमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां अदा की जाती हैं, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से संबंधित हैं। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्ध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब रायल्टियां अदा करने वाला स्वयं राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थायी प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियां अदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी रायल्टियां उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, वहां पर ऐसी रायल्टियां उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां अदाकर्ता और हितभाग स्वामी के बीच उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों की रकम, इसके उपयोग अधिकार अथवा सूचना, जिसके लिए इसकी अदायगी की गई थी, उस रकम से बढ़ जाती है अतः रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच सहमति हुई होती वहां, इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गई रकमों के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए ऐसे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाता रहेगा।

अनुच्छेद-14

पूंजीगत लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में यथा-उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तर्ण में प्राप्त अभिलाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तर्ण में होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तर्ण में होने वाले अभिलाभों पर, जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसी स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा भुक्तमल उद्यम के माध्यम) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तर्ण में होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, ऐसे अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तर्ण में अथवा ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अन्तर्ण में होने वाले अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी

राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

4. किसी ऐसी कंपनी के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी संपत्ति किसी संविदाकारी राज्य में स्थित मुख्यतः अचल संपत्ति है, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा। किसी ऐसी भागीदारी अथवा किसी व्यास के कारण व्याज के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी संपत्ति किसी संविदाकारी राज्य में स्थित मुख्यतः अचल संपत्ति है, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. पैराग्राफ 1, 2, 3 और 4 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

अनुच्छेद—15

स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतन्त्र स्वरूप वाले उसी तरह के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होगी:

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो, उस मामले में, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में उस अवधि अथवा अवधियों, जो भारत गणराज्य के मामले में संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" में अथवा फिलीपीन गणराज्य के मामले में "कैलेण्डर वर्ष" में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक न हो, के लिए उपस्थित रहता है।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद की अर्थ-विस्तार के अन्तर्गत स्वतन्त्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दंत-चिकित्सकों तथा लेखापालों के स्वतन्त्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद—16

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17 (निदेशकों की फीस), 18 (मनोरंजनकर्ता तथा खिलाड़ी), 19 (सरकारी सेवाएं), 20 (गैर-सरकारी पेशन तथा वाणिज्यिक), 21 (विद्यार्थी तथा प्रशिक्षु और 22 (प्रोफेसर तथा अध्यापक) के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी

द्वारा किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उक्त नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो ऐसे नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि:

(क) प्राप्तकर्ता, भारत गणराज्य के मामले में संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा फिलीपीन गणराज्य के मामले में "कैलेण्डर वर्ष" में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो;

(ख) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की जाती है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और

(ग) पारिश्रमिक, किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो उस नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन के संबंध में उस पर सवार होकर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद—17

निदेशकों की फीस

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक-मंडल के एक सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त की गई निदेशक फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद—18

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं) तथा 16 (पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं) के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा एक मनोरंजनकर्ता जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियों अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा एक संगीतकार अथवा एक खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो कर किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो तो उस स्थिति में उस आय पर अनुच्छेद 7 (कारोबार में लाभ), 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं) तथा 16 (पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं) के उपबंधों के होने हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यक्रमों किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होने हुए भी किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैसियत में किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों से अर्जित आय प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कराधेय होगी यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के कार्यक्रमों का सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच किसी विशेष कार्यक्रम के अनुसरण में किए गए हों, तथा प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधि अथवा किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सांविधिक निकाय अथवा लाभ-निरपेक्ष संगठन की निधियों से पर्याप्ततः समर्थित हों तथा जिन्हें उक्त राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस उपबंध के अध्याधीन अर्हताकारी रूप में प्रमाणित किया गया हो।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7 (कारोबार में लाभ), 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं), तथा 16 (पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं) के उपबंधों के होने हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसी हैसियत में किसी संविदाकारी राज्य में किए गए व्यक्तिगत कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी यदि किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए दो संविदाकारी राज्यों के बीच किसी विशेष कार्यक्रम के अनुसरण में किए गए हों, तथा उस दूसरे राज्य की सार्वजनिक निधि, किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सांविधिक निकाय अथवा किसी लाभ-निरपेक्ष संगठन की निधियों से पर्याप्ततः समर्थित हों तथा जिन्हें उक्त दूसरे राज्य, जिसका वह निवासी है, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्हताकारी रूप से प्रमाणित किया गया हो।

अनुच्छेद—19

सरकारी सेवा

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के निमित्त प्रवत, पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा;

(ख) लेकिन ऐसे पारिश्रमिक पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं तथा वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, जो—

(i) उस राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवासी नहीं बना था।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित की गई निधि में से किसी व्यक्ति को उस संविदाकारी राज्य के द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के निमित्त की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किसी पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा;

(ख) लेकिन ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा यदि वह व्यक्ति उक्त दूसरे राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 16 [पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं] तथा 17 [निदेशकों की फीस] तथा 20 (गैर-सरकारी पेंशन तथा वापिकियां) के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कारोबार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद—20

गैर-सरकारी पेंशन तथा वापिकियां

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थिति स्वतंत्रता से प्राप्त किसी भी प्रकार की पेंशन परन्तु अनुच्छेद 19 में उल्लिखित किसी पेंशन से भिन्न, अथवा किसी भी प्रकार की वापिकियों पर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

2. "पेंशन" पद का अभिप्राय पिछली सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान लगी चोटों की क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली किसी आवधिक अदायगी से है।

3. “वार्षिकी” पद से अभिप्राय, धन अथवा धन के मूल्य के रूप में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिकूल की एवज में दायित्वों के अध्यधीन जीवन-पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट अथवा निश्चित समयावधि के दौरान निश्चित समय पर आवधिक आधार पर निश्चित राशि की अदायगी से है।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है,

निम्नलिखित पर उसे दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी :

(क) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसे की गई अदायगियां ; और

(ख) भारत गणराज्य के मामले में किसी “पूर्ववर्ती वर्ष” अथवा फिलीपीन गणराज्य के मामले में, “कैलेंडर वर्ष” के दौरान उस दूसरे राज्य में नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक, जो 15,000 रुपए से अथवा फिलीपीन की मुद्रा में इसके समतुल्य से अधिक नहीं हो बशर्ते कि ऐसा नियोजन प्रत्यक्षतः उसके अध्ययन से संबंधित हो अथवा उसके भरण-पोषण के प्रयोजनार्थ किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होगा जो शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु इस अनुच्छेद का लाभ किसी व्यक्ति को किसी भी हालत में में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुँचने की तारीख से लगातार तीन वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में उल्लिखित राशियों की समय-समय पर समीक्षा दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी और उस पर सहमति दी जाएगी।

अनुच्छेद-22

प्रोफेसर तथा अध्यापक

1. किसी प्रोफेसर अथवा अध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय

अथवा किसी अन्य अनुमोदित संस्थान में शिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है अथवा था, उसके उक्त दूसरे राज्य में पहुँचने की तारीख से दो वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा अनुसंधान के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद ऐसे अनुसंधान से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा अनुसंधान मूलतः किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों विशेष के निजी लाभ के लिए किया गया हो।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह भारत गणराज्य के मामले में “पूर्ववर्ती वर्ष” अथवा फिलीपीन गणराज्य के मामले में “कैलेंडर वर्ष” में उस संविदाकारी राज्य का निवासी है, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा “पूर्ववर्ती वर्ष” अथवा “आय वर्ष” से तत्काल पूर्व दौरा करता है।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ “अनुमोदित संस्थान” से अभिप्राय ऐसे संस्थान से है, जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस बारे में अनुमोदित किया गया हो।

अनुच्छेद-23

अन्य आय

किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों पर जहाँ-कहीं वे उद्भूत होती हैं और जिनके बारे में इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, उस राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद-24

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय पर कराधान के मामलों में लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ पर इस करार में उनके विपरीत प्रावधान किया जाना है।

2. फिलीपीन के कानूनों के अध्यधीन तथा इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा फिलीपीन में उद्भूत हुए लाभों अथवा आय के संबंध में, जिस पर भारत और फिलीपीन, दोनों ही देशों में कर लगाया जा सकता है, देय फिलीपीन के कर की राशि, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो अथवा उसकी कटौती की गई हो, पर ऐसे लाभों अथवा आय के संबंध में देय भारतीय कर के

लिए जमा-खाते की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी राशि भारतीय कर (ऐसे जमा-खाते, की अनुमति दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित) की राशि से अधिक नहीं हो, जो फिलीपीन में उद्भूत हुए लाभों अथवा आय के अनुकूल हो। इसके अलावा, जहां कोई निवासी ऐसी कंपनी हो, जिसके द्वारा भारत में अतिकर की अदायगी की जाती है ऐसी स्थिति में भारत में उस कंपनी द्वारा देय आयकर तथा भारत में उस कंपनी द्वारा देय अतिकर पर अधिशेष, यदि कोई हो, पर प्रथमतः उपर्युक्त जमा-खाते की अनुमति दी जाएगी।

3 "देय फिलीपीन कर" पद में फिलीपीन कर की वह राशि भी शामिल मानी जाएगी, जिसे उस स्थिति में अदा किया गया होता यदि उद्भूत अभिसमय के अनुसार तथा इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को अथवा मौजूदा कानूनों में संशोधन करके अथवा उनमें परिवर्तन करके अविष्य में लागू किए जाने वाले फिलीपीन के कर कानूनों के अनुसार फिलीपीन में आर्थिक विकास के संवर्द्धन के लिए बनाए गए विशेष प्रोत्साहनकारी कानूनों के अनुसार फिलीपीन कर की छूट नहीं दी गई होती अथवा कटौती नहीं की गई होती।

4. भारत के कानूनों के अध्याधीन तथा इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार फिलीपीन के किसी निवासी द्वारा भारत में उद्भूत हुए लाभों अथवा आय के संबंध में, जिस पर भारत और फिलीपीन दोनों ही देशों में कर लगाया जा सकता, देय भारतीय कर की राशि, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से ही दी गई हो अथवा उसकी कटौती की गई हो, पर ऐसे लाभों अथवा आय के संबंध में देय फिलीपीन कर के लिए जमा-खाते की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी राशि फिलीपीन कर (ऐसे जमा-खाते की अनुमति दिए जाने से यथा संगणित) की राशि से अधिक नहीं हो, जो भारत में उद्भूत हुए लाभों अथवा आय के अनुकूल हो।

5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित जमा-खाते के प्रयोजनार्थ, "देय भारतीय कर" पद में कोई भी ऐसी राशि शामिल सम्मिलित जाएगी, जो किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में अदा की जाने योग्य होती यदि जिसके लिए, आर्थिक विकास के संवर्द्धन के प्रयोजनार्थ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अध्याधीन अथवा भारत में आर्थिक विकास के संवर्द्धन के प्रयोजनार्थ मौजूदा उपबंधों में संशोधन करते हुए अथवा परिवर्धन करते हुए एतदुपस्थात् लागू किए जाने वाले विशेष प्रोत्साहनकारी उपायों के अध्याधीन उस वर्ष के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए, कर से छूट अथवा कटौती की अनुमति नहीं दी गई होती।

अनुच्छेद-25

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा

तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो इस कराधान और संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर समान परिस्थितियों में लागू होती हैं अथवा लागू हो सकती हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य के समान कार्यों में लगे हुए उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में लगाया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य ऐसे व्यक्तियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत छूटें, राहतें, घटौतियां और कटौतियां प्रदान करने को बाध्य होगा, जो कानूनन केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, जो वहां के निवासी हैं।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समान उद्यमों पर समान परिस्थितियों के अधीन लागू हैं अथवा लागू हो सकती हैं।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, दोनों संविदाकारी राज्य आवश्यक कारोबार अथवा व्यापार के संवर्द्धन के मामले में उस राज्य द्वारा अपने राष्ट्रिकों को दिए गए कर के प्रोत्साहनों के लाभ को प्रतिबन्धित कर सकते हैं।

6. इस अनुच्छेद में "कराधान" पद से वे कर अभिप्रेत हैं, जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद—26

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यकलापों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, वह इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो उस स्थिति में वह उन राज्यों के आन्तरिक कानूनों द्वारा मुहैया किए गए उपायों के होते हुए भी, अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवासी है

अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के अध्वधीन आता है, तो उस संविदाकारी राज्य को प्रस्तुत करेगा जिसका कि वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे ऐसा कराधान उद्भूत होता है, जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक समाधान करने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा।

3. इस अभिसमय के अर्थ-निर्माण अथवा उसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे ऐसे मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श भी कर सकते हैं, जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है और जो इस अभिसमय के विषय हैं।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त पैराग्राफ के अधिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब किसी समझौते पर पहुंचने के लिए विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसा आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद—27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का (जिसमें दस्तावेज भी शामिल हैं) आदान-प्रदान करेंगे, जो इस अभिसमय के उपबंधों के अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से सम्बन्धित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जो कर इस अभिसमय के अन्तर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान-व्यवस्था, विशेष रूप से ऐसे करों की धोखाधड़ी अथवा अपवर्जन को रोकने के लिए इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। लेकिन यदि उक्त सूचना को, सूचना भेजने वाले राज्य में मूल रूप से गुप्त समझा जाता है, तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और

प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो उन करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में अन्तर्गस्त हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल उक्त प्रयोजनों के लिए ही करेंगे परन्तु वे उक्त सूचना को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा, जिसमें जहां-कहीं उपयुक्त हो, कर के परिहार के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी तौर पर किया जाएगा अथवा किसी मामले-विशेष के संदर्भ में अनुरोध के आधार पर अथवा दोनों तरह से किया जाएगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी नेमी आधार पर प्रस्तुत की जाने वाली सूचना अथवा दस्तावेजों की सूचना पर समय-समय पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का वह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित उत्तरदायित्व डाला जाए:—

(क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;

(ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद—28

राजनयिक एजेंट तथा कांसुली अधिकारी

इस अभिसमय की किसी भी बात से राजनयिक एजेंटों अथवा कांसुली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करों के उपबंधों के अंतर्गत विये गये वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद—29

प्रवर्तन

दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य, इस अभिसमय को लागू करने के लिए अपनी विधि के अंतर्गत अपेक्षित कार्य विधियों के पूरा किए जाने के बारे में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा। यह अभिसमय इन अधिसूचनाओं में से बाद में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से लागू होगा और इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा :

- (क) भारत में, उम कैलेण्डर वर्ष के, जिसमें बाद वाली अधिसूचना दी गई है, अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष से उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;
- (ख) फिलीपीन में, उस कैलेण्डर वर्ष के, जिसमें बाद वाली अधिसूचना दी गई है, अगले अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में।

अनुच्छेद—30

समाप्ति

यह अभिसमय अतिश्वितकाल तक लागू रहेगा लेकिन दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष के जून माह के तीसवें दिन को, अथवा उससे पहले, राजनयिक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को इसकी समाप्ति का लिखित रूप में नोटिस दे सकेगा और ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा :-

- (क) भारत में, उस कैलेण्डर वर्ष के, जिसमें सूचना दी जाती है, अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में ;
- (ख) फिलीपीन में, उस कैलेण्डर वर्ष के, जिसमें समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, अगले अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, हमके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने, इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

सन् एक हजार नौ सौ नब्बे में फरवरी माह के बारहवें दिन को मनीला में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, जिसके दोनों पाठ समानतः

प्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण में भिन्नता के मामले में, अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी रहेगा।

(सतीश चन्द्र)

भारत का राजदूत
भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

(हेमुस प. एस्तानिस्लाओ)

वित्त सचिव
फिलीपीन गणराज्य की
सरकार की ओर से

प्रोटोकॉल

1. अनुच्छेद 1 के प्रयोजनार्थ इस अभिसमय की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य को अपने स्वदेशी कानूनों के अनुसार अपने नागरिकों, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में रह रहे हैं, पर कर लगाने से रोका जा सके।¹ लेकिन ऐसे स्वदेशी कानूनों के अनुसरण में अदा किए गए संदेय करों को इस अभिसमय के अध्यक्षीन जमा खाते की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।

2. अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य के बाहर किए गए खर्चों के संबंध में कटौती को उस सीमा तक प्रतिबन्धित किया जाएगा, जितनी सीमा की अनुमति संबंधित संविदाकारी राज्य के अपने कानून में ऐसे खर्चों के लिए दी गई है।

3. अनुच्छेद 8 और 9 के पैराग्राफ 2 के प्रयोजनार्थ इनमें निर्धारित की गई कर की दर में, दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा आयद किए जाने वाले "शाखा लाभ प्रेषण कर" को शामिल समझा जाएगा।

4. अनुच्छेद 8 और 9 के प्रयोजनार्थ यदि इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् फिलीपीन किसी भी समय किसी तीसरे देश के साथ कर की निम्न दरें अथवा शून्य दर रखने के लिए सहमत होता है तो उस स्थिति में फिलीपीन गणराज्य की सरकार राजनयिक माध्यमों से भारत सरकार को अविलम्ब यह सूचना देगी तथा दोनों सरकारें, दोनों संविदाकारी राज्यों के उद्योगों द्वारा समान परिस्थितियों के अध्यक्षीन प्राप्त किए जा रहे समान किस्म के लाभों पर कर की ऐसी निम्न दरें अथवा शून्य दरों की व्यवस्था करने के लिए इन अनुच्छेदों की समीक्षा करेंगी।

जिसके साक्ष्य में, हमके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

सन् एक हजार नौ सौ नब्बे में फरवरी माह के बारहवें दिन को मनीला में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, जिसके दोनों पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण में भिन्नता के मामले में, अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी रहेगा।

(सतीश चन्द्र)

भारत का राजदूत
भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

(हेमुस प. एस्तानिस्लाओ)

वित्त सचिव
फिलीपीन गणराज्य की
सरकार की ओर से

[सं. 10041/96 फा. सं. 501/7/74 एफ.टी.डी.]

एन.पी. साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 1996
(Income-tax)

G.S.R. 173(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Philippines for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has entered into force on the 21st March, 1994, after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Convention in accordance with Article 29 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA
AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PRE-
VENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of the Philippines,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes of income imposed on behalf of each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

3. The taxes to which this Convention shall apply are :

(a) in India :

- (i) the income tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ;
- (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) ;
(herein referred to as "Indian tax").

(b) in the Philippines :—The income taxes imposed by the Government of the Republic of the Philippines ;
(herein referred to as "Philippine tax").

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws,

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and air space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law/the U.N. Convention on the Law of the Sea ;
- (b) the term "Philippines" means the Republic of the Philippines and when used in a geographical sense means the national territory comprising the Republic of the Philippines ;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or the Philippines as the context requires ;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Philippine tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes ;
- (e) the term "person" includes an individual, a company and any other taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States ;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States ;
- (g) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State ;
- (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative ; and in the case of the Philippines, the Secretary of Finance or his authorized representative ;
- (i) the term "national" means any individual, possessing the citizenship of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State ;
- (j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

If the place of effective management cannot be determined, then the competent authorities shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a place of exploration of natural resources;
- (h) a building site or construction project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activity continues for a period of more than six months;
- (i) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this

combination is of a preparatory or auxiliary character.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State (other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies) shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if :

- (a) he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 3 of this Article ; or
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- (c) in so acting, he manufactures or processes in that State for the enterprise goods or merchandise belonging to the enterprise.

5. An insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other State if it collects premiums in the territory of that State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not agent of an independent status.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of the enterprise, he shall not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph if it is shown that the transactions between the agent and the enterprise were not made under arms-length conditions. In such a case, the provisions of paragraph 4 shall apply.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute for either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, live-stock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on

business, as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of the Convention, then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, profits from sources within a Contracting State derived by an enterprise of the other Contracting State from the operation of aircraft in international traffic may be taxed in the first-mentioned State in accordance with its domestic law, but the tax so charged shall be reduced by forty per cent. In no case, however, shall the tax so charged exceed the lowest rate of Philippine tax that may be imposed on profits of the same kind derived under similar circumstances by a resident of a third State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

SHIPPING

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, profits from sources within a Contracting State derived by an enterprise of the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the first-mentioned State in accordance with its domestic law, but the tax so charged shall be reduced by forty per cent. In no case, however, shall the tax so charged exceed the lowest rate of Philippine tax that may be imposed on profits of the same kind derived under similar circumstances by a resident of a third State.

853 GI/96—3.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least ten per cent of the shares of the company paying the dividends ;
- (b) 20 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount of interest if the interest is received by a financial institution (including insurance companies);
- (b) the Philippine tax on interest paid by a company which is a resident of the Philippines to a resident of India in respect of public issues of bonds, debentures or similar obligations shall not exceed 10 per cent of the gross amount of interest ; and
- (c) 15 per cent of the gross amount of interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2—

- (a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

- (i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State ; or
- (ii) the Central Bank of the other Contracting State;

- (iii) other lending institutions as may be specified and agreed in letters exchanged between the competent authorities of the Contracting States.

- (b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person [other than a person referred to in sub-paragraph (a)] who is a resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, including sales on credit of any industrial, commercial or scientific equipment, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of the Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties provided that such royalties are payable :

- (i) in the case of Philippines, by an enterprise which is registered with the Board of Investment, and
- (ii) in the case of India, by an enterprise in pursuance of any collaboration agreement approved by the Government of India.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use right or information for which they are paid exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the

payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, referred to in Article 6, and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of a company, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State, may be taxed in that State. Gains from the alienation of interest in a partnership or a trust, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State, may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" in the case of Republic of India or "calendar year" in the case of Republic of the Philippines.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists, and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17 (Directors' Fees), 18 (Entertainers and Athletes), 19 (Government Service), 20 (Non-Government Pensions and Annuities), 21 (Students and Trainees) and 22 (Professors and Teachers), salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" in the case of Republic of India or "calendar year" in the case of the Republic of the Philippines;
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State

Article 18

ENTERTAINERS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 (Independent Personal Services) and 16 (Dependent Personal Services), income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as theatre, motion picture, radio or television artist or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. While income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 (Business Profits), 15 (Independent Personal Services) and 16 (Dependent Personal Services), be taxed in the

Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are exercised pursuant to a special programme between the Governments of the two Contracting States for cultural exchange and are supported substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State or a political sub-division, or a local authority thereof or from the funds of a statutory body, or a non-profit organisation which is certified as qualifying under this provision by the competent authority of that State.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7 (Business Profits), 15 (Independent Personal Services), and 16 (Dependent Personal Services), where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State if such activities are exercised by an entertainer or athlete of that other Contracting State pursuant to a special programme between the Governments of the two Contracting States for cultural exchange and are supported substantially from the public funds of that other State, a political sub-division or a local authority thereof or from the funds of a statutory body, or a non-profit organisation which is certified as qualifying by the competent authority of that other State of which he is a resident.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :—

(i) is a national of that State ; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3 The Provisions of Articles 16 (Dependent Personal Services), 17 (Directors' Fees) and 20 (Non-Government Pensions and Annuities) shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

Article 20

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The terms "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 21

STUDENTS AND TRAINEES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on :—

(a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training ; and

(b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding Rs. 15,000 or its equivalent in Philippine currency during any "previous year" in the case of Republic of India or "Calendar year" in the case of the Republic of the Philippines, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than three consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

3. The amounts referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article may be reviewed and agreed upon by the competent authorities of both Contracting States from time to time.

Article 22

PROFESSORS AND TEACHERS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved Institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" in the case of Republic of India or "calendar year" in the case of the Republic of the Philippines, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "year of income".

4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 23

OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provision to the contrary are made in this Convention.

2. The amount Philippine tax payable, under the laws of the Philippines and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of profits or income arising in the Philippines, which have been subjected to tax both in India and in the Philippines, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Indian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in the Philippines. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance

against income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India.

3. The term "Philippine tax payable" shall be deemed to include the amount of Philippine tax which would have been paid if the Philippine tax had not been exempted or reduced in accordance with this Convention and the special incentive laws designed to promote economic development in the Philippines, effective on the date of signature of this Convention, or which may be introduced in the future in the Philippine taxation laws in modification of, or in addition to, the existing laws.

4. The amount of Indian tax payable under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of the Philippines, in respect of profits or income arising in India, which has been subjected to tax both in India and the Philippines, shall be allowed as a credit against Philippine tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Philippine tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in India.

5. For the purposes of the credit referred to in paragraph 4, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax for any assessment year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof by the special incentive measures under the provisions of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which are designed to promote economic development, or which may be introduced hereafter in modification of, or in addition to, the existing provisions for promoting economic development in India.

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the

first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, either Contracting State may, in the promotion of necessary industry or business, limit to its nationals the enjoyment of tax incentives granted by it.

6. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the provisions of the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention relating to the taxes which are the subject of this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, in so far as the taxation

thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after

the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given;

- (b) in the Philippines, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect:

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice is given;
- (b) in the Philippines, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Manila this twelfth day of February one thousand and nine hundred and ninety in Hindi and English languages, both the text being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

(SATISH CHANDRA)

Ambassador of India

For the Government of
the Republic of India.

(JESUS P. ESTANISLAO)

Secretary of Finance

For the Government of the
Republic of the Philippines.

PROTOCOL

1. For purposes of Article 1, nothing in this Convention shall be construed as preventing either Contracting State from taxing its citizens, in accordance with its domestic legislation, who may be residing in the other Contracting State. However, no credit shall be given under this Convention for taxes paid/payable in pursuance of such domestic legislation.

2. For purposes of paragraph 3 of Article 7, the deductions in respect of expenses incurred outside the Contracting State shall be restricted as per the limitation on allowance of such expenses provided in the domestic law of the concerned Contracting State.

3. For purposes of paragraph 2 of Articles 8 and 9, the rate of tax prescribed therein is understood to include the Branch Profit Remittance Tax as may be leviable by either Contracting State.

4. With reference to Articles 8 and 9 if at any time after the date of signature of the Convention the Philippines agrees to a lower or nil rate of tax with a third State the Government of the Republic of the Philippines shall without undue delay inform the Government of India through diplomatic channels and the two Governments will undertake to review these Articles with a view to providing such lower or nil rate to profits of the same kind derived under similar circumstances by enterprises of both Contracting States.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Manila this twelfth day of February one thousand nine hundred and ninety in Hindi and English languages, both the texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

(SATISH CHANDRA)

Ambassador of India

For the Government of
the Republic of India.

(JESUS P. ESTANISLAO)

Secretary of Finance

For the Government of the
Republic of the Philippines
(No. 10041/96-F. No. 501/7/74-FTD)
N.P. SAHNI, Jr. Secy.

